

87/1014

तारीख
हुसम

हुसम या कार्यवाही अथ इतिशियत्य जज

29/8/2015

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थनी अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 से 2/1 से 2/8 के अधिवक्ता उपस्थित। शेष विप्रार्थी एकपक्षीय। उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थनी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थनी की पुश्तैनी भूमि ग्राम टापरा की खसरा संख्या 1063/450 क्षेत्रफल 2.4767 हैक्टर एवं ग्राम भाखरी खेड़ा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 147/9 क्षेत्रफल 3.2375 हैक्टर भूमि अवस्थित है। विवादित भूमि प्रार्थनी के पिता भैराराम के नाम वक्त सेटलमेंट दर्ज हुए थी। भैराराम के फौत होने पर उसके वारिसान मे प्रार्थनी का भी नाम दायर किया जाना चाहिए था,लेकिन प्रार्थनी को उसके हक हकूको से महरूम रखते हुए विवादित भूमि मे प्रार्थनी का नाम दर्ज नहीं किया गया,जबकि प्रार्थनी का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। विवादित भूमि मे प्रार्थनी का नाम दायर नहीं होने का नाजायज फायदा उठाकर विप्रार्थी प्रार्थनी को मौके से बेदखल करने एवं भूमि को बेचान करने पर उतारू है। यदि इसमे सफल हो गए तो प्रार्थनी के वाद का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। अतः प्रार्थनी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मूलवाद के निर्णय तक विवादित भूमि की राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखे जाने का स्थगन आदेश पारित किया जावे। इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थनी की ओर से मनगढन्त तथ्यो के आधार पर आवेदन पेश किया गया है,जो चलने योग्य नहीं है। क्योकि प्राथनी का विवादित भूमि मे कोई हक हकूक निहित नहीं है। विवादित भूमि पुश्तैनी नहीं है और न ही विवादित भूमि पर प्रार्थनी का कब्जा काश्त रहा है। भैराराम के फौत हुए लगभग 25 वर्षो का समय व्यतीत हो चुका है,इतने वर्षो तक प्रार्थनी क्यो चुपचाप रही,क्यो नहीं कानूनी कार्यवाही की गई,इस संबध मे कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि प्रार्थनी की ओर से विप्रार्थी को परेशान करने की नियत से वाद पेश किया गया है,जिसमे प्रार्थनी को सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है। जबकि विप्रार्थी रेकर्डेड खातेदारा है और रेकर्डेड खातेदार के विरुद्ध स्थगन आदेश जारी नहीं किया जा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

87/2024


सकता है। अतः प्रार्थनी का आवेदन गलत तथ्यों के आधार पर होने के कारा खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दरतावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूलवाद में खातेदारी घोषणा व स्थाई निष्ठाज्ञा जारी करवाने का अनुतोष चाहा गया है, जो कि मूलवाद में साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर तय होगा कि वादीनी/प्रार्थनी राहत प्राप्त करने के हकदार है अथवा नहीं। लेकिन हस्तगत प्रकरण में स्थगन आदेश को जारी रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि प्रार्थनी न ही विवादित भूमि की रिकार्डेड खातेदार है, जबकि विप्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है और रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध स्थगन आदेश जारी नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पहुंचा है कि प्रथम दृश्यता मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थनी के पक्ष में नहीं बनते हैं।

लिहाजा प्रार्थनी का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कस्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ़तर हो।


सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा
29/08/2024